



2026:AHC:56518

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 10987 वर्ष 2026

श्री चित्रांश कंस्ट्रक्शन बबीना, प्रोपराइटर राजीव खरे के माध्यम सेआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी गण

आवेदक के अधिवक्ता : शिव कुमार सिंह

विपक्षी गण के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान धारा 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट 1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा परिवाद संख्या 14512 वर्ष 2025 (मेसर्स कुमार ट्रेडर्स बबीना प्रोपराइटर शिव कुमार गुप्ता के माध्यम से बनाम श्री चित्रांश कंस्ट्रक्शन बबीना प्रोपराइटर राजीव शिव कुमार श्री खरे के माध्यम से), अंतर्गत धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, थाना बबीना, जिला झांसी में पारित सम्मन आदेश दिनांक 15.05.2025 को रद्द करने हेतु दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पक्षों के बीच पैसों का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि मामला पैसों के भुगतान के संबंध में है, इसलिए समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच.', 2010 (5) एससीसी 663 में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है। प्रासंगिक पैराग्राफ 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, 'सम थॉट्स टुवर्ड्स लॉ रिफॉर्म्स ऑन द टॉपिक ऑफ सेक्शन 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट-टैकलिंग एन एवलांच ऑफ केसेस' (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5]:

'...अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ दंड (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन का भुगतान सुनिश्चित करने का एक साधन अधिक है। शिकायतकर्ता की रुचि चेक जारी करने वाले को जेल में देखने के बजाय मुख्य रूप से अपना पैसा वसूलने में होती है। जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के विरुद्ध जो जेल की सजा काटने को तैयार है, चेक धारक के पास उपचार के रूप में बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं।

यदि हम दायर की गई शिकायतों की संख्या की जांच करें जो अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'तय' हो गई, और दूसरी ओर वे मामले जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचे, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा सुलझा लिया गया और केवल बहुत कम संख्या में मामले जारी रहे।'

18. यह काफी स्पष्ट है कि चेक बाउंस होने के अपराध के संबंध में, उपचार के दंडात्मक पहलू की तुलना में प्रतिपूरक पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान महान्यायवादी द्वारा जताई गई आशंकाओं को भी कुछ समर्थन मिलता है कि अधिकांश चेक बाउंस मामलों में वास्तव में शमन के माध्यम से समझौता या निपटारा किया जा रहा है, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में, जिससे न्याय वितरण में अनुचित देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जिसमें वे विवाद को सुलझाने के साधन के रूप में शमन को बहुत देरी से चुनते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान महान्यायवादी का तर्क है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार मजिस्ट्रेटों द्वारा शिकायतों का संज्ञान लेने के तुरंत बाद विकल्प चुनने के बजाय, अंतिम उपाय के रूप में शमन को चुन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं और फिर समझौते का रास्ता तभी चुनते हैं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हालांकि इस तरह के व्यवहार को मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन कठोर तथ्य यह है कि शमन चुनने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों में लंबित बकाया मामलों में योगदान देती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से निपटान या समझौता करने को तैयार है, तो यह आम तौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ योग्यता का संकेत है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों में ही शमन को चुनें। हालांकि, यदि अभियुक्त के पास अन्य आधारों के अलावा गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसा कोई वैध बचाव है, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है। ”

5. अधिवक्ता के अनुरोध पर, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करते हुए एक आवेदन दे सकता है और चेक राशि का 10% जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन दिए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है और अभियुक्त को आगे अवसर प्रदान करेगा जो इस दिशा में प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात, न्यायालय आज से पांच महीने की अवधि के भीतर विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'दामोदर एस. प्रभु' (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगा।
6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होकर मुकदमे का सामना करना होगा और न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार आगे बढ़ने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी कठोर दंडात्मक कदम नहीं अपनाया जाएगा।
8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उसी अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में यह आवेदन दिया गया है।
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

मीनू सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।